

मुख्यमंत्री

प्रदेश में इस बार मॉनसून ने भारी तबाही मचाई है और प्राकृतिक आपदा से राज्य को करोड़ों रूपए का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावितों को रहने के लिए 5 हजार रुपये मासिक किराया देने का एलान किया है। आज शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस मॉनसून की भारी वर्षा, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं से राज्य में अब तक 7 सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर उन्होंने आज गृहमंत्री अमित शाह से भी बात की है जिस पर उन्होंने हिमाचल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला जिला में जुब्बल उपमंडल की झगटान पंचायत में 9 करोड़ 40 लाख रूपए की लागत से निर्मित गलछु –कोदू –गारली सड़क का आज उदघाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से पंचायत के झालटा और धानसर जैसे सीमावर्ती गांव के लोगों को लाभ होगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि जुब्बल-नावर कोटखाई में चार सौ करोड़ रूपए से विभिन्न सड़क निर्माण और उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। इससे पहले उन्होंने 20 लाख रूपए की लागत से बने सरस्वती नगर के पंचायत भवन का भी शुभारंभ किया।

राहत बचाव

प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम आज थमा रहा, जिससे पिछले दिनों भारी बरसात से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य में तेजी आई है। मौसम विभाग ने राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में कल से 8 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश, बादल फटने व भूस्खलन के कारण प्रभावित मंडी जिला के थुनाग, धर्मपुर और जंजैहली में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा राहत व पुनर्वास कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं। उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि बगस्याड़ क्षेत्र के लिए राशन की पांच सौ किटें और थुनाग क्षेत्र के रेण गलू व पखरैर पंचायतों सहित अन्य क्षेत्रों में लोगों को राशन व रसोई गैस सिलेण्डर पहुंचाए गए हैं। उन्होंने बताया कि उफनते नदी नालों को पार कर स्वयं सेवियों, स्थानीय लोगों व विभागीय कर्मचारियों और संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रभावित लोगों तक आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि बाढ़ व बादल फटने से प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र के अतिदुर्गम गांव पियाला डिजी से एनडीआरएफ की टीम ने 65 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है।

हिमकेयर

राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत प्रत्येक वर्ष तिमाही आधार पर कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत इस माह से पंजीकरण के लिए पोर्टल खुला है। प्रवक्ता ने बताया कि इन कार्डों की वैधता एक वर्ष होगी और आवेदन के लिए ये पोर्टल हर तीन महीने बाद खोला जाएगा। हालांकि हिमकेयर कार्ड धारक पूरे वर्ष में कभी भी नवीनीकरण करवा सकते हैं।
